मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

बजरंगियों ने अपराध की आड़ में माहौल खराब करने का प्रयास किया 2
किसानों को सरकार बर्बाद करने पर तुली तो जनता करेगी सफाया 4
वीनस फैक्ट्री के मालिकान ने एक मज़दूर की जान ले ली 5
कश्मीर में सेना के कर्नल, मेजर और पुलिस के डीएसपी की शहादत 6
ईएसआई मेडिकल कॉलेज पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का छापा बेकार गया 8

वर्ष 37 | अंक -44 | फरीदाबाद | 17-23 सितम्बर 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

खट्टर ने भ्रष्ट निगम के आगे हथियार डाले, खारिज किया 160 करोड़ का सीवर लाइन प्रोजेक्ट

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम में लगातार घोटालों के खुलासे होने से डरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़खल-एनआईटी क्षेत्र में नई सीवर लाइन डाले जाने की 160 करोड़ रुपये की योजना खारिज कर दी। दिखाने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं लेकिन सच्चाई मुंह से निकल ही गई बोले, मुझे मालूम है स्थानीय नेता नगर निगम का पैसा खा रहे हैं, यह सुनकर केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर से लेकर बड़खल विधायक सीमा त्रिखा और मंत्री मूलचंद के चेहरे उतर गए।

खट्टर ग्रीवेंस कमेटी बैठक में जन सुनवाई के बाद जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। चुनावी वर्ष का आगाज होने के कारण सभी जन प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में बचे हुए विकास कार्य जल्द कराने पर जोर दे रहे थे। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार विधायक सीमा त्रिखा ने बड़खल व एनआईटी में 160 करोड़ रुपये

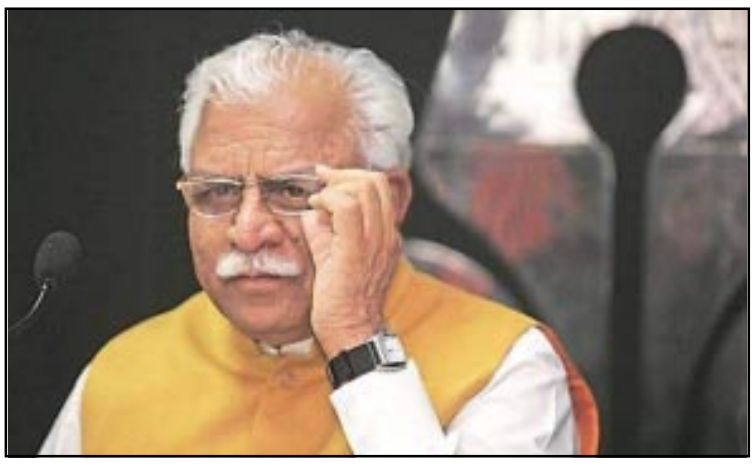

की सीवर लाइन योजना के लिए पैसों की मांग कर दी। इस पर मुख्यमंत्री खट्टर भड़क गए और नगर निगम में विकास कार्यों के नाम पर हो रही लूट कमाई पर नाराजगी जताते हुए बोले कि मुझे सब पता है यहां के लोकल नेता नगर निगम को लूट कर खा रहे हैं। ये नेता विकास कार्य नहीं होने दे रहे, मैं पैसे भेजता हूं ये खा जाते हैं। सीवर लाइन के लिए मेरे पास 160 करोड़ रुपये नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम ने नगर निगम के कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट को भी पैसा नहीं होने की बात कह कर रोक दिया।

यह सूबे के मुखिया की लाचारी और कमजोरी ही कही जाएगी कि जानते हुए भी वह अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पाए, केवल 'कड़ी निंदा' से अपनी भड़ास निकाल कर शांत हो गए। उन्हें अपने भ्रष्ट नेता तो दिखे लेकिन बीते नौ साल से विकास के नाम पर ठगी जा रही जनता का कोई ख्याल नहीं आया। एनआईटी ही नहीं पूरे शहर की अहम समस्या बन चुके सीवेज सिस्टम को दुरुस्त कराने के बजाय "ईमानदार और कर्मठ" खट्टर ने योजना को पैसा देने से ही इनकार कर दिया।

यदि वह सच में ईमानदार हैं तो जनहित में सीवेज सिस्टम की योजना के लिए न सिर्फ पैसा जारी करें बल्कि उसे गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा करवाएं। लेकिन उनके ही शब्दों में 'नगर निगम को लूटने वाले स्थानीय नेताओं' के रहते उनके लिए यह मुमकिन नहीं है और उनमें इतना दम भी नहीं है कि इन भ्रष्ट नेताओं से अधिकार छीन कर उन्हें उनकी औकात बताएं और परेशान जनता की समस्याओं का समाधान बिना भ्रष्टाचार करा पाएं।

कई साल से हो रहीं सिर्फ घोषणाएं

बड़खल-एनआईटी की पुरानी सीवर लाइनों को बदले जाने का ढिंढोरा कई साल से पीटा जा रहा है, वर्ष 2018 में चुनावी वर्ष शुरू होते ही सौ करोड़ रुपये से यह सीवर लाइन डालने का ढिंढोरा पीटा गया। सरकार बनने के बाद 2020 में फिर से 115 करोड़ रुपये की घोषणा की गई, यहां तक बताया गया कि सरकार ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है।

2021 में एक बार फिर 127 करोड़ रुपये की लागत से बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने का ढोल पीटा गया। दिसंबर 2022 में खट्टर की मौजूदगी में एक बार फिर 160 करोड़ रुपये की सीवर लाइन परियोजना की घोषणा की गई। अब खट्टर ने खुद ही इसे खारिज कर बता दिया कि भाजपाई काम नहीं बल्कि काम का नाम लेकर जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हैं।

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया, घोटाला तो होगा ही

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत संविदा पर भर्ती नगर निगम के जूनियर इंजीनियरों की आय तो महज 33 हजार रुपये प्रति माह है लेकिन इनकी जीवनशैली किसी लखपति से कम नहीं है। सिफारिश और भाई-भतीजावाद के जोर पर नगर निगम में पद हासिल करने वाले जेई के खिलाफ अधिकारी भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। कई जेई तो ठेकेदारों से पार्टनरशिप किए हैं जबकि कुछ तो छद्मनाम से खुद ही ठेकेदारी कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि ठाठ-बाट वाले अफसरों के होते हुए नगर निगम दो सौ करोड़ के बड़े और हर सप्ताह किसी छोटे घोटाले का गढ़ कैसे बना।

मुख्यमंत्री खट्टर की ईजाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के जरिए नगर निगम में 33 जेई संविदा पर तैनात हैं। इनका वेतन वर्तमान में 33 हजार रुपये प्रतिमाह बताया जा रहा है। ये सभी जेई दस से बीस लाख रुपये कीमत की कार के मालिक हैं, अधिकतर के पास एक से डेढ़ लाख रुपये कीमत वाले स्मार्टफोन हैं तो महंगे गैजेट्स भी हैं। महंगे गैजेट्स से लेकर ब्रांडेड कपड़े और अधिकारियों से भी महंगी कारों से घूमने वाले अधिकतर जूनियर इंजीनियर नियमों को ताक पर रख मनमर्जी से काम करते हैं।

भाजपा नेताओं के करीबी और उनकी सिफारिश पर नौकरी पाए इन इंजीनियरों को लूट कमाई वाले पद भी दे दिए गए। केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर के करीबी बताए जाने वाले प्रवीण बैंसला लंबे समय से तोड़फोड़ विभाग संभाले हैं। कहने को तो यह नगर निगम के जेई हैं लेकिन चलते सत्ता के इशारे पर हैं, यानी तोड़फोड़ के दौरान इन्हें भी विपक्षी पार्टी के समर्थकों का अतिक्रमण दिख जाता है लेकिन आका और उनके चाटुकारों का नहीं। लगातार विवाद में रहने के बावजूद किसी निगमायुक्त में संविदा के इस जेई से तोड़फोड़ का चार्ज लेने की हिम्मत नहीं हुई। पूर्व निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया ने तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र के साथ उसे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का तोड़फोड़ इंचार्ज बना दिया था। तोडफोड़ विभाग का यह पद अत्यधिक मलाईदार समझा जाता है।

इसी तरह जेई मनोज को सभी रैनीवेल का चार्ज सौंपा गया था, जेनरेटर चलाने के नाम पर प्रतिमाह लाखों रुपये की हेराफेरी करने के बावजूद उसे इस पद पर बना रहने दिया गया। नगर निगम में सबको मालूम है कि रैनीवेलों के मेनटेनेंस के ठेके भी छद्मनाम से मनोज ने ही ले रखे हैं। मनोज की ही तरह निगम के अनेक जेई ठेकेदारों के पार्टनर हैं। अपने चहेते ठेकेदार को काम दिलाने के कमीशन के साथ ही पार्टनरशिप का मुनाफा भी काट रहे हैं। स्कूटी पर चलने वाले संदीप कुमार ने जेई बनते ही शहर की पॉश सैनिक कॉलोनी में महंगा घर खरीद लिया। शायद यही कारण है कि नगर निगम आए दिन कंगाल बनता जा रहा है जबकि अधिकारी व कर्मचारी मालामाल है।

सरकारी नियम के मुताबिक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना आला अधिकारी की अनुमति ड्यूटी स्टेशन नहीं छोड़ सकता। नगर निगम के ये रंगबाज जेई ड्यूटी समय खत्म होते ही अपनी महंगी कार में बैठ कर दूसरे जिलों को कूच कर जाते हैं। जेई मनोज, देवेंद्र, विपिन, अरुण, दिनेश आर्य, परवेज आलम और कपिल रोजाना पलवल से आते- जाते हैं, यानी

विवादित जेई नं. 1 : प्रवीन बैंसला

प्रतिमाह 3690 रुपये तो केवल टोल टैक्स के रूप में चुका देते हैं, पेट्रोल-डीजल का खर्च अलग। जेई अजीत बंचारी से, रविंदर मिंडकौला से, वीर सिंह जनौली से तो विपिन कुमार भगोला से आते हैं। जेई शिवकुमार तो उत्तर प्रदेश के जेवर से प्रतिदिन कार से आते जाते हैं।

खैर, संविदा पर तैनात ये जेई तो जिला मुख्यालय छोड़ेंगे ही जब अतिरिक्त निगमायुक्त गौरव आंटिल ही रोजाना गुड़गांव भाग जाते हैं।

ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम में वीर सिंह नामक व्यक्ति एचकेआरएन से तैनात नहीं होने के बावजूद बीते छह माह से बतौर जेई काम कर रहा है, जबकि उसको वेतन नहीं मिलता, जाहिर है अधिकारियों ने उसे उगाही के लिए यह अवैतनिक पद दे रखा है।

नगर निगम में भ्रष्टाचार का रोना रोने वाले सीएम खट्टर और उनका एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों इतने कमजोर हैं कि सत्ता के घाघ नेताओं और उनके इशारों पर चलने-पलने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। रोना रोने से तो निगम में न भ्रष्टाचार खत्म होगा और न ही भ्रष्ट अधिकारी काबू में आएंगे।

अगर खट्टर की नीयत ठीक होती और वाकई भष्टाचार से निपटना चाहते तो यह तो मिनटों-सेकेंडों का काम है, अफसरों और कर्मचारियों की क्या औक़ात लेकिन इसके लिए साफ नीयत चाहिए, सब जानते हैं कि सीएम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बहाने हर महीने अपने एजेंट से मिलने आते हैं।